भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2122
***
(जिसका उत्तर मंगलवार, 22 मार्च, 2022/1 चैत्र, 1944 (शक) को दिया जाना है।)

"वर्ष 2022 के लिए असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए बजट आवंटन"

2122. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वर्ष 2022 के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है;
(ख) इस योजना वर्ष में सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए कौन-कौन सी नई योजनाओं एवं परियोजनाओं की संस्वीकृत दी गई हैं; और
(ग) सरकार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए बजट आवंटन का उपयोग यहां के किन-किन प्रमुख क्षेत्रों में करने जा रही है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): वित्त मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों को उनकी पात्रता और कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार धन जारी करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आबंटन प्रदान करता है। असम और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के राज्यों को आबंटन/निर्गमन के निर्णय संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा लिए जाते हैं। वर्ष 2021-22 (संशोधित अनुमान) के दौरान असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को ₹ 68440.26 करोड़ का आबंटन है। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान 16.03.22 तक की स्थिति के अनुसार ₹ 36334.57 करोड़ (असम को ₹ 7858.85 करोड़ सहित) वित्त आयोग अनुदान जारी किया है।

(ख): वित्तीय वर्ष **2021-22 (**फरवरी, **2022)** के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) द्वारा उसकी विभिन्न योजनाओं, नामतः पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी), पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना (एनईआरडीएस), गैर-व्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर), पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस), असम का विशेष पैकेज (बीटीसी, डीएचएटीसी और केएएटीसी) की योजनाएं, पहाड़ी क्षेत्र कार्यक्रम (एचएडीपी**)**, पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (एनईएसआरआईपी**)** और सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि (एसआईडीएफ**)** के तहत अब तक ₹ **198.34** करोड़ की **28** नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ग): पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकार के प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कृषि एवं किसान कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, बिजली, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र शामिल हैं।

***